

वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण

अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2009-10 के उत्तरार्द्ध में 7.9 प्रतिशत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर्ज की और केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) द्वारा 8 फरवरी, 2010 को जारी किए गए अग्रिम अनुमानों के आंकड़ों के अनुसार समग्र वर्ष 2009-10 में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज किए जाने का अनुमान है। वैश्विक वित्तीय संकट उत्पन्न होने के बाद की अनिश्चित अवधि जो वैश्विक आर्थिक मंदी में परिवर्तित हुई और जिसके परिणामस्वरूप 2008-09 की तीसरी और चौथी तिमाहियों में और चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में त्रैमासिक वृद्धि दर 6 प्रतिशत के आस पास रहने के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी आई थी, के बाद हुई तीव्र वृद्धि मजबूत देश के वृहद आर्थिक सिद्धांतों और मध्यावधिक संदर्भ में उज्ज्वल आर्थिक संभावनाओं को रेखांकित करती है। चालू वर्ष के लिए अनुमानित वृद्धि का स्तर पुनरुत्थानशील औद्योगिक क्षेत्र से प्रेरित था और इसे थोड़ा ही सही कृषि क्षेत्र में गिरावट रहने के बावजूद हासिल किया गया था। सकल घरेलू उत्पाद के मांग पक्ष पर, 2009-10 की दूसरी तिमाही में सकल पूंजी निर्माण में हुई वृद्धि एक व्यापक पुनरुद्धार दर्शाती है। खाद्य और खाद्य वस्तुओं में मुद्रास्फीति के बढ़े हुए स्तर जो व्यापक रूप से आपूर्ति पक्ष की अवरुद्धता और कमजोर दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण हुए कहे जा सकते हैं, बड़ी चिंता का कारण है क्योंकि इससे स्फीतिकारी संभावनाओं के माध्यम से सामान्य मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। हाल के आंकड़ों के अनुसार वाणिज्य वस्तु निर्यातों, पूंजी प्रवाहों और बैंक/खाद्य-भिन्न ऋण में बढ़ोतरी वित्तीय बाजारों में उत्साह की वापसी के चलते आर्थिक पुनरुद्धार अच्छा हुआ है।

2. सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने 2008-09 के त्वरित अनुमान प्रस्तुत करते हुए अपनी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएस) का आधार वर्ष संशोधित करके 1999-2000 से 2004-05 किया है। 2004-05 की श्रृंखला के अनुसार अर्थव्यवस्था में 2007-08 में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि के पश्चात 2008-09 में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। 2009-10 के अग्रिम अनुमानों में उपादान लागत पर और 2004-05 की स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में हुई वृद्धि 44,53,064 करोड़ रुपए, वर्तमान बाजार कीमतों पर सकल घरेलू वृद्धि 61,64,178 करोड़ रुपए मानी गई है।

वर्ष 2008-09 में संशोधित श्रृंखला के अनुसार कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्रों के स.घ.उ. के 1999-2000 की श्रृंखला में क्रमशः 17.0 प्रतिशत और 57.3 प्रतिशत के हिस्से के मुकाबले 15.7 प्रतिशत और 56.4 प्रतिशत हिस्से के चलते अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन आया है। उद्योग का हिस्सा 1999-2000 की श्रृंखला में 25.8 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 की नई श्रृंखला में 28.0 प्रतिशत हो गया है जो आर्थिक संरचना के लिए अपेक्षित संतुलन का कुछ पैमाना बताता है। इन हिस्सों के चलते चालू वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों के वृद्धि के स्तर विकास में बिन्दुगत योगदान का निर्धारण करते हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि कृषि में पिछले वर्ष हासिल किए गए 0.2 प्रतिशत स्तर की तुलना में गिरावट आने का अनुमान है, अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए चालू वित्त वर्ष में कृषि-भिन्न क्षेत्रों में 8.5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की जरूरत है। वर्ष 2009-10 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार निर्माण क्षेत्र का अपवाद छोड़कर अन्य सभी उप-क्षेत्रक बेंचमार्क स्तर के निकट अथवा अधिक हैं। वर्ष 2009-2010 में बिजली, गैस एवं जलापूर्ति, सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं और होटल, परिवहन तथा संचार की वृद्धि दर क्रमशः 8.2, 8.2 और 8.3 प्रतिशत पर बेंचमार्क से मामूली कम है। 2009-10 में 7.2 प्रतिशत पर उत्पादन वृद्धि उपर्युक्त को प्रतिबिम्बित करती है।

सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) के मांग पक्ष की ओर 2008-09 में और चालू वित्त वर्ष (2009-10) में निवल अप्रत्यक्ष करों (अर्थात् सब्सिडियां घटाकर अप्रत्यक्ष कर) में गिरावट कर राहत के माध्यम से वित्तीय प्रोत्साहन कर प्रभाव और सब्सिडियों के स्तर में वृद्धि इंगित करता है। एनएस श्रृंखला में परिवर्तन से भी 2008-09 के स.घ.उ. के व्यय अनुमानों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। 2008-09 में सरकार के अंतिम उपभोग व्यय में वृद्धि अधोमुखी संशोधित की गई जो पुराने आधार में 2008-09 में 20 प्रतिशत से अधिक से नए आधार में 16.7 प्रतिशत पर आ गया जबकि 2008-09 में निजी अंतिम उपभोग व्यय की वृद्धि ऊर्ध्वमुखी संशोधित कर 2.9 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत की गई थी। 2009-10 में निजी अंतिम उपभोग व्यय में वृद्धि 4.1 प्रतिशत और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में वृद्धि 8.2 प्रतिशत रखी गई है। सकल घरेलू बचत और सकल पूंजी निर्माण को सामान्यतया चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। संशोधित श्रृंखला के अनुसार सकल घरेलू बचतों के 2007-08 में 36.4 प्रतिशत से गिरकर 2008-09 में 32.5 प्रतिशत रहने और सकल पूंजी निर्माण (निवेश की दर) 2007-08 में 37.7 प्रतिशत से गिरकर 2008-09 में 34.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। हालांकि, सकल नियत पूंजी निर्माण 2008-09 और 2009-10 में 33.0 प्रतिशत पर स्थिर बना रहा। सकल नियत पूंजी निर्माण में वृद्धि 2008-09

में 4 प्रतिशत से सुधर कर 2009-10 में 5.2 प्रतिशत होने का अनुमान है। हालांकि, 2009-10 की तीसरी और चौथी तिमाहियों में निजी निवेश में वृद्धि समुत्थान और प्रोत्साहन उपायों की आंशिक वापसी के प्रभाव पर नजर रखना जरूरी है। निवल निर्यात, जो अब धनात्मक है, का अंशदान औद्योगिक समुत्थान की गहनता के चलते आयात मांग के बढ़ने और घरेलू मांग के गति पकड़ने से पुनः ऋणात्मक हो सकता है।

कृषि उत्पादन

आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी कृषि उत्पादन के चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन के 2007-08 में 230.78 मिलियन टन की तुलना में 2008-09 में 233.88 मिलियन टन होने का अनुमान था। दक्षिण पश्चिम मानसून में दीर्घावधि औसत की तुलना में 23 प्रतिशत की कमी ने 2009-10 के खरीफ मौसम में बुआई को बुरी तरह प्रभावित किया। खाद्यान्नों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र 2009-10 के खरीफ मौसम में पिछले वर्ष के इसी मौसम की तुलना में 6.5 प्रतिशत कम रहा है। 2009-10 के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार खरीफ मौसम में खाद्यान्नों का उत्पादन 98.83 मिलियन टन होने का अनुमान है जो धान की सर्वाधिक प्रभावित फसल के चलते 2008-09 के चौथे अग्रिम अनुमानों की तुलना में 16 प्रतिशत की गिरावट इंगित करता है। खरीफ के रकबे में हुई हानियों के एक हिस्से को रबी मौसम में रकबा बढ़ाकर पूरा किए जाने की संभावना है। उपलब्ध अद्यतन अनुमानों के अनुसार गेहूँ, दालों और मूंगफली के अंतर्गत बुआई क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष (4 फरवरी, 2010 तक) अधिक है। 2009-10 में गन्ने का उत्पादन 249.48 मिलियन टन होने का अनुमान है जो पिछले की तुलना में 9 प्रतिशत और 2009-10 के लक्षित उत्पादन की तुलना में 27 प्रतिशत कम है। 2009-10 में कपास का उत्पादन 236.57 लाख गांठें (प्रत्येक 170 किलोग्राम) होने का अनुमान है जो चौथे अग्रिम अनुमानों में 2008-09 में 231.56 लाख गांठों से 2.2 प्रतिशत अधिक है। फिर भी, यह 2009-10 के लिए निर्धारित 9 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में कम है।

औद्योगिक उत्पादन

स.घ.उ. के तिमाही अनुमानों से संग्रहित अर्थव्यवस्था में समुत्थान उद्योग में पुनरुत्थान के कारण है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के अनुसार अद्यतन सूचना में भी यह प्रतिबिंबित हुआ है। चालू वित्त वर्ष में दिसंबर, 2009 में चौथी बार आईआईपी ने 10 प्रतिशत का आंकड़ा पार किया है। दिसंबर 2009 में आईआईपी 16.8 प्रतिशत (दिसंबर, 2008 में - 0.2 प्रतिशत की तुलना में) बढ़ा है - जो हालिया विगत में वृद्धि का सबसे ऊंचा स्तर है। यह अगस्त 2009 में 10.6 प्रतिशत, अक्टूबर, 2009 में 10.3 प्रतिशत और नवंबर, 2009 में 11.7 प्रतिशत के बाद हुआ है। 17 उद्योग समूहों में से चौदह समूहों ने 2-अंकीय स्तर पर दिसंबर 2008 की तुलना में दिसंबर 2009 के दौरान धनात्मक वृद्धि दर्शायी है। आईआईपी में संचयी वृद्धि अप्रैल-दिसंबर, 2008 के दौरान 3.6 प्रतिशत की तुलना में 8.6 प्रतिशत हुई थी। यह अप्रैल-दिसंबर 2009 में विनिर्माण में 9.0 प्रतिशत, खनन में 8.5 प्रतिशत और बिजली में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि से संघटित हुआ है जो अप्रैल-दिसंबर 2008 में क्रमशः 3.6 प्रतिशत, 3.2 प्रतिशत और 2.7 प्रतिशत के स्तरों की तुलना में है। दूरसंचार सेवाओं की सुदृढ़ वृद्धि की गति की अगुआई में विद्युत, कोयला और पत्तन, नागर विमानन और सड़कों जैसी अन्य अवसंरचना, बड़े उद्योग और अवसंरचना सेवाओं ने भी 2009-10 में समुत्थान के लक्षण दिखाए हैं।

मुद्रास्फीति

वर्षानुवर्ष आधार पर थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के संबंध में मापित मुद्रास्फीति अगस्त 2008 के 12.8 प्रतिशत से तीव्रतापूर्वक गिरकर मार्च 2009 में 1.2 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2009-10 में औसत वार्षिक मुद्रास्फीति (अप्रैल-दिसंबर) वर्ष 2008-09 के 10.2 प्रतिशत के मुकाबले 1.6 प्रतिशत रही। अप्रैल 2009 में चालू वित्त वर्ष (2009-10) की शुरुआत 1.3 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर से हुई और जून से अगस्त 2009 तक यह ऋणात्मक रही। दिसम्बर 2009 में वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति विगत वर्ष के इसी माह के 6.1 प्रतिशत के मुकाबले 7.3 प्रतिशत रही। दिसम्बर 2009 में समग्र थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति का लगभग 7 प्रतिशत भाग खाद्य वस्तुओं (मूलभूत और विनिर्मित) की वजह से रहा, इसके बाद ईंधन और विद्युत पण्य समूह की वजह से 12 प्रतिशत का स्थान आता है, शेष 21 प्रतिशत भाग विनिर्मित खाद्य-भिन्न और मूलभूत खाद्य-भिन्न वस्तुओं की वजह से रहा। मुद्रास्फीति में दूध (20 प्रतिशत), अंडे, मांस और मछली (20 प्रतिशत से अधिक), चावल (लगभग 10 प्रतिशत), गेहूँ (6 प्रतिशत), दलहन (लगभग 9 प्रतिशत), आलू (9 प्रतिशत) और टमाटर (6 प्रतिशत) का प्रमुख योगदान रहा।

दिसंबर 2009 के दौरान औद्योगिक कामगारों के संबंध में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति एक वर्ष पहले की 9.7 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत हो गई। थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दरों में हाल की अवधि में महत्वपूर्ण अंतर देखा गया है जो मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के खाद्य समूह में दिए गए अधिक महत्व के कारण और खुदरा मूल्यों में अपेक्षाकृत गिरावट की वजह से रहा। इस प्रकार, अनिवार्य वस्तु मूल्यों में तीव्र वृद्धि के कारण सभी चार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मार्च 2008 से लगभग 7 से 8 प्रतिशत (माह-दर-माह) से क्रमिक रूप से बढ़कर दिसम्बर 2009 में लगभग 15-17 प्रतिशत हो गए।

इस मुद्रास्फीति की एक महत्वपूर्ण वजह कुछ अनिवार्य वस्तुओं में आपूर्ति संबंधी अड़चनें और विलम्ब और सामान्य से कम आए दक्षिण-पश्चिम मानसून के साथ-साथ देश के कुछ भागों में सूखे जैसी स्थिति भी रही। विलम्बित और अनिश्चित मानसून की वजह से गेहूँ से भिन्न अधिकांश खाद्य वस्तुओं के मूल्यों की मौसमी गिरावट, जो अक्टूबर से मार्च की अवधि के दौरान सामान्यतः देखी जाती है, में रुकावट रही होगी। दिसम्बर 2009 से खाद्य वस्तुओं के उच्च मूल्यों के साथ-साथ अप्रशासित ईंधन उत्पाद मूल्यों की क्रमिक बढ़ोतरी से अन्य खाद्य-भिन्न वस्तुओं के मूल्यों में भी बढ़ोतरी हुई और इस प्रकार अगले कुछ माह में प्रत्याशा से अधिक सामान्य मुद्रास्फीति के संबंध में संभावना होने से कुछ चिंताएं उत्पन्न हुई हैं।

3. वैदेशिक क्षेत्र

भारत के पण्यगत निर्यात में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय लचीलापन देखा गया है और वर्ष 2002-03 से अमरीकी डालर में 20 प्रतिशत की वृद्धि दर रही। संशोधित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2008-09 में निर्यात वृद्धि 13.6 प्रतिशत रही। वित्त वर्ष 2009-10 की शुरुआत में वैश्विक मंदी का पूर्ण प्रभाव देखा गया। वर्ष 2008-09 की पहली छमाही के निर्यात आंकड़ों के उच्च आधार स्तरों से वर्षानुवर्ष आधार पर निर्यात में अत्यधिक गिरावट देखी गई (अप्रैल-नवम्बर 2008-09 में 22.3 प्रतिशत)। नवम्बर 2009 में निर्यात में निरंतर 12 माह की ऋणात्मक वृद्धि के पश्चात 18.2 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। हालांकि, यह नवम्बर, 2008 के निम्न आंकड़ा आधार के कारण रही (अक्टूबर 2008 के 14.1 बिलियन डालर और दिसम्बर 2008 के 13.4 बिलियन डालर के मुकाबले 11.2 बिलियन डालर)। दिसम्बर 2009 में निर्यात वृद्धि दर दिसम्बर 2008 के मुकाबले 9.3 प्रतिशत घनात्मक रही। वर्ष 2009-10 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान आयात वृद्धि 23.6 प्रतिशत पर ऋणात्मक थी और पीओएल और पीओएल-भिन्न आयात में क्रमशः 29.8 प्रतिशत और 20.7 प्रतिशत की गिरावट रही। सोने और चांदी के आयात में 7.3 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। औद्योगिक गतिविधियों और निर्यात में मंदी के कारण पीओएल-भिन्न गैर-बुलियन आयात में 22.4 प्रतिशत की गिरावट रही। दिसम्बर 2009 में आयात वृद्धि 27.2 प्रतिशत पर घनात्मक रही जो आंशिक रूप से आधार प्रभाव, आंशिक रूप से तेल मूल्यों और औद्योगिक मांग में तेजी के साथ पीओएल उत्पादों के 42.8 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि तथा आंशिक रूप से सोने और चांदी के आयात में उच्च वृद्धि के साथ पीओएल-भिन्न वस्तुओं की 22.4 प्रतिशत वृद्धि की वजह से हुई। वर्ष 2009-10 (अप्रैल-दिसम्बर) में व्यापार घाटा विगत वर्ष की इसी अवधि के 106 बिलियन अमरीकी डालर से गिरकर 76.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

सेवा निर्यात

वर्ष 2008-09 में सेवा निर्यात पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 12.5 प्रतिशत से बढ़कर 102 अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गए। यह वृद्धि विविध सेवा श्रेणी में काफी अच्छी रही है, जिनका हिस्सा 2000-01 के स्तर की तुलना में 2008-09 में 16.1 प्रतिशतांक बढ़कर 76.4 प्रतिशत हो गया। सॉफ्टवेयर सेवाओं का हिस्सा जहां 6.5 प्रतिशतांक बढ़कर 45.5 प्रतिशत हो गया वहीं सॉफ्टवेयर-भिन्न सेवाओं का हिस्सा 9.6 प्रतिशतांक बढ़कर 30.9 प्रतिशत हो गया। विविध सेवाओं की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर 2000-01 से 2006-07 के दौरान काफी अधिक 33.4 प्रतिशत थी, जिसके बाद 2007-08 और 2008-09 में इनकी वार्षिक वृद्धि दरें क्रमशः 21.3 प्रतिशत और 15.9 प्रतिशत थी। वैश्विक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा निर्यातों पर दृष्टिगोचर था जिनमें 2009-10 की पहली छमाही में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 27.6 प्रतिशत की उच्च वृद्धि की तुलना में 21.4 प्रतिशत तक की गिरावट आई। बीमा को छोड़कर, सभी मदों में ऋणात्मक वृद्धि दिखाई दी।

भुगतान सन्तुलन

वित्त वर्ष 2009-10 के लिए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, भुगतान संतुलन आधार पर निर्यात और आयात में 2009-10 के अप्रैल-सितम्बर (पूर्वाद्ध) के दौरान 2008-09 में इसी अवधि की तुलना में काफी अधिक गिरावट दिखाई दी। तथापि 2008-09 के पूर्वाद्ध की तुलना में 2009-10 के पूर्वाद्ध के दौरान भुगतान सन्तुलन परिदृश्य में सुधार हुआ है जो उच्चतर निवल पूंजी अंतर्प्रवाहों और निम्नतर व्यापार घाटे में प्रतिबिम्बित होता है। अप्रैल-सितम्बर, 2008 में 64.4 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2009 के प्रथमाद्ध (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान व्यापार घाटा 58.2 बिलियन अमरीकी डालर पर कम था जो मुख्यतया तेल निर्यात में कमी के कारण था। भुगतान-सन्तुलन आधार पर निर्यात में 2009-10 के पूर्वाद्ध (अप्रैल-सितम्बर 2009) में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 48.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 27.0 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। अप्रैल-सितम्बर 2009 के दौरान आयात भुगतानों में 20.6 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में इसमें 51.0 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई थी। आयात में गिरावट के लिए मुख्य रूप से तेल की कीमतों में मूल प्रभाव और गिरावट उत्तरदायी है।

अप्रैल-सितम्बर 2008 के दौरान 48.5 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में अप्रैल-सितम्बर 2009 के दौरान निवल अदृश्य अधिशेष (अदृश्य प्राप्तियां घटा अदृश्य भुगतान) 39.6 बिलियन अमरीकी डालर पर कमतर थे। निम्नतर व्यापार घाटे के बावजूद, अप्रैल-सितम्बर 2008 में 15.8 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में, अप्रैल-सितम्बर 2009 में चालू खाता घाटा बढ़कर 18.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जो मुख्यतया निम्नतर निवल अदृश्य प्राप्तियों के कारण था।

भारत को निवल पूंजी प्रवाह अप्रैल-सितम्बर 2008 में 12.0 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में अप्रैल-सितम्बर 2009 में 29.6 बिलियन अमरीकी डालर के उच्च स्तर पर थे। निवल पूंजी प्रवाहों के अंतर्गत ऋण और बैंकिंग पूंजी के अतिरिक्त सभी घटकों में पिछले वर्ष की समान अवधि के स्तर से अप्रैल-सितम्बर 2009 के दौरान सुधार दिखाई दिया। अप्रैल-सितम्बर, 2009 के दौरान निवल अन्तर्वाही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 21.0 बिलियन अमरीकी डालर पर उच्च बने रहे (अप्रैल-सितम्बर 2008 में 20.7 बिलियन अमरीकी डालर) जो भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहतर संवृद्धि निष्पादन को परिलक्षित करता है। बड़ी मात्रा में अन्तर्वाही एफडीआई के कारण निवल एफडीआई (अन्तर्वाही एफडीआई घटा बहिर्गामी एफडीआई) अप्रैल-सितम्बर 2009 में 14.1 बिलियन अमरीकी डालर पर मामूली रूप से अधिक थे जो भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहतर संवृद्धि निष्पादन को परिलक्षित करता है। पोर्टफोलियो निवेश, जिसमें मुख्यतया विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के निवेश और अमरीकी निक्षेपागार प्राप्तियां (एडीआर/वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियां) शामिल हैं, में मुख्यतया भारतीय पूंजी बाजार में एफआईआई द्वारा व्यापक खरीदों के कारण अप्रैल-सितम्बर 2009 में बहुत अधिक निवल अन्तर्प्रवाह (17.9 बिलियन अमरीकी डालर) (अप्रैल-सितम्बर 2008 में 5.5 बिलियन अमरीकी डालर का निवल बहिर्प्रवाह) दिखाई दिया, जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि की संभावनाओं की बहाली और वैश्विक निवेश के माहौल में सुधार को प्रतिबिम्बित करता है।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां (एफसीए), स्वर्ण, एसडीआर और आरक्षित ट्रान्श स्थिति शामिल हैं। मार्च 1991 के अन्त में 5.8 बिलियन अमरीकी डालर के निम्न स्तर से आरंभ होकर भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार मई 2008 के अन्त में बढ़कर 314.61 बिलियन अमरीकी डालर के शीर्ष स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद मार्च 2009 के अन्त में भण्डार घटकर 252.0 बिलियन अमरीकी डालर रह गया। जनवरी 2010 के अन्त में विदेशी मुद्रा भंडार 281.0 बिलियन अमरीकी डालर था। वर्ष 2009-10 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने, नवम्बर 2009 में 6.7 बिलियन अमरीकी डालर की लागत पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सीमित स्वर्ण बिक्री कार्यक्रम के तहत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 200 मीट्रिक टन सोना खरीदा है। इसके अतिरिक्त, क्रमशः 28 अगस्त, 2009 और 9 सितम्बर 2009 को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत को 3082 मिलियन एसडीआर (4821 मिलियन अमरीकी डालर के समकक्ष) सामान्य आवंटन और 214.6 मिलियन एसडीआर (340 मिलियन अमरीकी डालर के समकक्ष) विशेष आवंटन किया गया। इसके अतिरिक्त, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अधीन अंतर्वाह, पोर्टफोलियो निवेश और अनिवासी भारतीय जमाराशियां तथा मुख्य मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डालर की कमजोरी के कारण मूल्यन लाभ भी 2009-10 में विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में योगदान देने वाले मुख्य स्रोत थे।

वित्त वर्ष 2009-10 में, मार्च 2009 के बाद, सुधार के लक्षणों और विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) प्रवाहों की वापसी से, अमरीकी डालर की तुलना में रुपया मजबूत हुआ है। वर्ष 2009-10 में विनिमय दर संबंधी घटनाक्रम ने संकेत दिया कि अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की औसत मासिक विनिमय दर की मूल्य वृद्धि मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमरीकी डालर के कमजोर पड़ने के कारण मार्च 2009 में 51.23 रुपये प्रति अमरीकी डालर से 11.5 प्रतिशत बढ़कर जनवरी 2009 में प्रति अमरीकी डालर 45.96 रुपये हो गई है।

4. मुद्रा, बैंकिंग और पूंजी बाजार

आर्थिक विकास मन्द होने के प्रत्युत्तर में मौद्रिक नीति की आवश्यकता के मद्देनजर, 2009-10 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक नीति विवरण, जिसकी घोषणा अप्रैल 2009 में की गई, में नीतिगत व्यवस्था प्रदान करना आशयित है, जो पर्याप्त नकदी प्रदान करेगी, क्रेडिट गुणवत्ता का संरक्षण करते हुए व्यवहार्य दरों पर क्रेडिट विस्तार करने में समर्थ बनाएगी ताकि अर्थव्यवस्था को उच्च विकास के मार्ग पर वापस लाने में सहायता मिल सके और मौद्रिक एवं ब्याज दर प्रणाली को मूल्य स्थिरता तथा वित्तीय स्थिरता के लिए सहायक बनाया जा सके।

यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक के 2009-10 (28 जुलाई 2009) के लिए मौद्रिक नीति की पहली तिमाही समीक्षा में अपनी समायोजनात्मक मौद्रिक स्थिति बनाए रखी, इसने नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया। मौद्रिक नीति 2009-10 (27 अक्टूबर 2009) की दूसरी तिमाही की समीक्षा में भी बैंक दर (6 प्रतिशत पर) रेपो तथा रिवर्स रेपो दर (क्रमशः 4.75 प्रतिशत और 3.25 प्रतिशत पर) और आरक्षित नकदी अनुपात (5.0 प्रतिशत पर) को अपरिवर्तित रखा गया। तथापि, सांविधिक नकदी अनुपात (एसएलआर) में लघु परिवर्तन किया गया और इसे 7 नवम्बर, 2009 से आरंभ होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की निवल मांग और मीयादी देनदारियों के 25 प्रतिशत पर पुनः बहाल किया गया (एसएलआर को 7 नवंबर 2008 को एससीबी के एनडीटीएल का 24 प्रतिशत पर कम कर दिया गया)।

मौद्रिक नीति 2009-10 (29 जनवरी, 2010) की तीसरी तिमाही की समीक्षा में, भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत स्थिति 'संकट प्रबंधन' करने से 'पुनरुद्धार प्रबंधन' में परिवर्तित करने की आवश्यकता द्वारा निर्मित हुई। यद्यपि स्फीतिकारी दबाव के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आपूर्ति पक्ष के कारकों को दोषी ठहराया गया, उसने महसूस किया कि इन दबावों को व्यापक स्फीतिकारी प्रक्रिया में फैलने को नियंत्रित करने की आवश्यकता है और इसलिए समुचित रूप से सावधानी की आवश्यकता है। एससीबी का आरक्षित नकदी अनुपात दो चरणों में उनके एनडीटीएल के 5.0 प्रतिशत से 5.75 प्रतिशत पर 75 आधार बिन्दु बढ़ा दिया गया; 50 आधार बिन्दु की पहले चरण की वृद्धि 13 फरवरी, 2010 से आरंभ होने वाले पखवाड़े से हुई, इसके बाद 25 आधार बिन्दु की अगली वृद्धि का चरण 27 फरवरी, 2010 से आरंभ होने वाले पखवाड़े से शुरू हुआ, चूंकि यह प्रणाली में अत्यधिक नकदी के वर्चस्व को प्रभावित करेगा।

तीसरी तिमाही की समीक्षा के अनुसार 2009-10 के लिए समायोजित खाद्य भिन्न क्रेडिट वृद्धि के लिए सांकेतिक अनुमान 16 प्रतिशत था। 2009-10 में स्थूल मुद्रा (एम3) वृद्धि हेतु सांकेतिक अनुमान 16.5 प्रतिशत था, जबकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियों में 17 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान था।

उभरती प्रवृत्तियों को देखते हुए वर्षानुवर्ष आधार पर स्थूल मुद्रा (एम3) की वृद्धि एक वर्ष पहले की 19.1 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले 15 जनवरी, 2010 की स्थिति के अनुसार 16.5 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष आधार पर एम3 में वृद्धि 2009-10 (15 जनवरी, 2010 तक) के दौरान 10.8 प्रतिशत थी जबकि यह पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि के दौरान 12.8 प्रतिशत थी। स्थूल मुद्रा की वृद्धि में हुई कमी मुख्यतः वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए जाने वाले बैंक ऋणों की वृद्धि में गिरावट होने के कारण है। वित्त वर्ष आधार (15 जनवरी, 2010 तक) पर आरक्षित मुद्रा (एम0) में एक वर्ष पहले की 3.7 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले 3.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जबकि वर्षानुवर्ष आधार पर यह पिछले वर्ष की 6.6 प्रतिशत की तुलना में 14.8 प्रतिशत बढ़ी है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान, बैंक ऋण में वृद्धि निम्न स्तर पर रही, खाद्य-भिन्न ऋण ने वित्त वर्ष (15 जनवरी, 2010 तक) के दौरान केवल 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जो अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों द्वारा लिए जाने वाले ऋण की मांग में निरन्तर मंदी को प्रदर्शित करता है। सांविधिक नकदी अनुपात प्रतिभूतियों की वाणिज्यिक बैंकों की जमा पूंजियां 15 जनवरी, 2010 की स्थिति के अनुसार एनडीटीएल का 29.9 प्रतिशत थीं जबकि मार्च 2009 के अन्त में ये 28.1 प्रतिशत और एक वर्ष पूर्व 28.8 प्रतिशत थीं। यह 7 नवम्बर, 2008 से एनडीटीएल के 24 प्रतिशत के नियत स्तर और 7 नवम्बर, 2009 के 25 प्रतिशत के मुकाबले निरन्तर उच्च बनी रही।

नकदी अड़चन वर्तमान में ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे मांग मुद्रा दरों की प्रवृत्ति से मापा जाए, जो रिपो तथा रिवर्स रिपो परिचालन के अन्तर्गत शासित हो, तथा मुद्रा बाजार भागीदारों के साथ रिवर्स रिपो नीलामियों के माध्यम से जो अपनी निधियों का निरन्तर संग्रह करते रहे हों। नीति/ब्याज दरें हाल में स्थिर रही हैं। बड़ी मात्रा में किए गए लेन-देन तथा निम्न जोखिम विस्तारों के साथ, वित्तीय बाजारों में हलचल देखी गयी; इक्विटी बाजारों में कभी कभार अस्थिरता के साथ उछाल देखा गया, विदेशी मुद्रा बाजारों में सुव्यवस्थित दशाएं बनी रहीं; तथा बड़ी मात्रा में सरकारी उधारों के कारण सरकारी प्रतिभूतियों की आय में कुछ ऊपरी दबाव देखा गया।

5. केन्द्र सरकार का वित्त पोषण

वर्ष 2007-08 तक एफआरबीएम अवधि में राजकोषीय समेकन मोर्चे पर प्राप्त प्रगति संतोषजनक रही है। वर्ष 2008-09 में विस्तारित नीतिगत स्वरूप कुल मांग को प्रोत्साहन देने में न्यायसंगत सिद्ध हुआ। वर्ष 2009-10 के लिए बजट अनुमानों में स.घ.उ. के 6.8 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के साथ विस्तारित स्वरूप की निरन्तरता की परिकल्पना की गयी है। वृहत् आर्थिक स्थिति पर बने दबाव हेतु वर्ष में प्रदत्त राजकोषीय प्रोत्साहन अन्तरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रक्रियाओं की तर्ज पर है। केन्द्र के सम्बन्ध में सकल कर - स.घ.उ. अनुपात जो एफआरबीएम पूर्व अवधि में लगभग 8-10 प्रतिशत की रेंज में स्थिर रहा, वह 2006-07 में बढ़कर 11.1 प्रतिशत और 2007-08 में स.घ.उ. का 12.0 प्रतिशत हो गया। 2009-10 के बजट में प्रोत्साहन के भाग के रूप में घोषित कर कटौतियों और मंदी के प्रभाव को देखते हुए इसके स.घ.उ. का 10.9 प्रतिशत (संशोधित स.घ.उ. का 10.4 प्रतिशत) का अनुमान लगाया गया है। राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की इसी अवधि से तुलना करने पर अप्रैल-दिसम्बर 2009-10 के दौरान 16.5 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। पूंजी व्यय में इस अवधि के दौरान 41.2 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई। 2009-10 के पहले नौ महीनों में कुल व्यय बजट अनुमान का 69.3 प्रतिशत था। ऋण भिन्न प्राप्तियां व्यय के केवल 56.2 प्रतिशत भाग को कवर करने के लिए पर्याप्त थीं, इस प्रकार 3,09,980 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा देखा गया। यह 2008-09 में अप्रैल-दिसम्बर के दौरान 2,18,262 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे से तुलना करने पर काफी अधिक है। राजस्व घाटा अप्रैल-दिसम्बर 2009-10 में 2,51,254 करोड़ रुपए था। यह भी इसी अवधि में 2008-09 में 1,73,830 करोड़ रुपए के आंकड़ों से तुलना करने पर काफी अधिक है। अप्रैल-दिसम्बर 2009-10 के दौरान ऋण भिन्न प्राप्तियां 2008-09 में इसी अवधि से तुलना करने पर 4.9 प्रतिशत तक बढ़ीं।

6. सम्भावनाएं

आर्थिक समुत्थान के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। सामान्य से कम मानसून के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में 0.2 प्रतिशत की गिरावट को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह समुत्थान विनिर्माण क्षेत्र की नई गति पकड़ने से हुआ है तथा साथ ही सकल निर्धारित पूंजी निर्माण जो 2008-09 में काफी घट गया था, की विकास दर में भी तेजी आयी है। सुधार की तीव्र गति तथा व्यापक स्वरूप ने संकट के पश्चात् सरकार के नीतिगत दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है। हाल का आर्थिक घटनाक्रम उभरती हुई आर्थिक स्थिति पर आधारित विस्तारवादी नीतिगत स्थिति की ओर क्रमबद्ध व्यवस्थित और सुस्पष्ट रूप से बढ़ने की दिशा में एक शुभ संकेत है। भारत मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में एक बड़ी अर्थव्यवस्था है जो ठोस मूलभूत शक्तियों के साथ संकट से तेजी से उबर सका है और इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था की ठोस विकास क्षमता समता आधार पर बड़ी मात्रा में दिए गए योगदान को दृष्टिगत रखते हुए उसकी वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भागीदारी का सूचक है। अल्पावधि में, मौजूदा प्रवृत्तियों की निरन्तरता के अनुमानों के अन्तर्गत, भारत की सम्भावनाएं वैश्विक संकट से पहले के तीव्र विकास के मार्ग पर जो 2008 में मंद पड़ गयी थी, वापस लौटने की दिशा में अत्यधिक उज्ज्वल हैं। मध्यावधि में वैश्विक अर्थव्यवस्था के जोर पकड़ने तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर संकेन्द्रित ध्यान दिए जाने से यह सम्भव है कि विकास दर को दो अंकीय स्तरों पर लाया जा सकेगा।

वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण
(आर्थिक कार्य निष्पादन : एक दृष्टि में)

क्र.सं.	मद	निरपेक्ष मूल्य		प्रतिशत परिवर्तन	
		अप्रैल-दिसम्बर		अप्रैल-दिसम्बर	
		2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
वास्तविक क्षेत्र					
1.	उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (हजार करोड़ रुपए)*				
	(क) वर्तमान मूल्यों पर	5229 त्व.अ.	5791 अ.अ.	15.1 त्व.अ.	10.8 अ.अ.
	(ख) 2004-2005 के मूल्यों पर	4155 त्व.अ.	4453 अ.अ.	6.7 त्व.अ.	7.2 अ.अ.
2.	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (1993-94=100)	270.8	294.2	3.6	8.6
3.	थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1993-94=100) ^क	235.8	239.7	10.2	1.6
4.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक: औद्योगिक कामगार (2001=100) ^क	144.0	160.0	9.0	11.4
5.	मुद्राआपूर्ति (एम3) (हजार करोड़ रुपए) ^क	4444	5209	19.9	17.2
6.	वर्तमान मूल्यों पर आयात ^क				
	(क) करोड़ रुपए	1126200	927969	52.2	-17.6
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	253809	193829	44.4	-23.6
7.	वर्तमान मूल्यों पर निर्यात ^क				
	(क) करोड़ रुपए	652920	563304	42.4	-13.7
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	147569	117587	29.6	-20.3
8.	व्यापार घाटा (मिलियन अमरीकी डालर) ^क	-106240	-76242
9.	विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां				
	(क) करोड़ रुपए में	1240161	1323235	14.3	6.7
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर में	255968	283470	(-)7.0	10.7
10.	चालू लेखा शेष (मिलियन अमरीकी डालर में) (अप्रैल-दिसम्बर)	(-)15849	(-)18618
सरकारी वित्त साधन (करोड़ रुपए में) ^क					
1.	राजस्व प्राप्तियां	3,75,937	3,89,271	5.7	3.5
2.	कर राजस्व (निवल)	3,09,927	3,07,591	4.7	-0.8
3.	कर-भिन्न राजस्व	66,010	81,680	10.7	23.7
4.	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	2,21,279	3,18,269	86.6	43.8
5.	ऋणों की वसूली	2,974	3,983	-10.0	33.9
6.	अन्य प्राप्तियां	43	4,306	-99.9	9914.0
7.	उधार और अन्य देनदारियां	2,18,262	3,09,980	181.3	42.0
8.	कुल प्राप्तियां (1+4)	5,97,216	7,07,540	25.9	18.5
9.	आयोजना-भिन्न व्यय (10+12)	4,26,419	4,97,381	26.5	16.6
<i>जिसमें:</i>					
10.	राजस्व खाता	4,03,758	4,60,970	44.2	14.2
<i>जिसमें:</i>					
11.	ब्याज भुगतान	1,23,735	1,30,005	10.7	5.1
12.	पूंजी खाता	22,661	36,411	-60.3	60.7
13.	आयोजना व्यय (14+15)	1,70,797	2,10,159	24.5	23.0
<i>जिसमें:</i>					
14.	राजस्व खाता	1,46,009	1,79,555	27.2	23.0
15.	पूंजी खाता	24,788	30,604	10.9	23.5
16.	कुल व्यय (9+13)	5,97,216	7,07,540	25.9	18.5
17.	राजस्व व्यय (10+14)	5,49,767	6,40,525	39.2	16.5
18.	पूंजी व्यय (12+15)	47,449	67,015	-40.2	41.2
19.	राजस्व घाटा (17-1)	1,73,830	2,51,254	343.3	44.5
20.	राजकोषीय घाटा {16-(1+5+6)}	2,18,262	3,09,980	181.3	42.0
21.	प्रारम्भिक घाटा (20-11)	94,527	1,79,975	-376.5	90.4

त्व.अ. त्वरित अनुमान; अ.अ. अग्रिम अनुमान

* पूर्व वर्ष से संबंधित

^क अप्रैल से दिसम्बर की औसत

^क एम₃ संबंधी आंकड़े वर्ष 2009-10 के लिए 18 दिसम्बर, 2009 की स्थिति के अनुसार और 2008-09 के लिए 19 दिसम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार दिए गए हैं।

^क सीमाशुल्क आधार पर; संशोधित आधार की तुलना में अनन्तिम आधार पर चालू वर्ष हेतु तुलनात्मक अध्ययन।

^क लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा संसूचित आंकड़े